नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 069
दि. 08.07.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'कुछ-कुछ होता है' से 'बहुत कुछ होता है' तक, पीएम मोदी ने इंडोनेशिया से दुनिया को दिखाई भारत की ताकत

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित किया और इस मंच से दुनिया को भारत की ताकत बताई।

पीएम मोदी ने भारत और इंडोनेशिया के मजबूत होते रिश्तों की भी बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं, तब कुछ-कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है।'

प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंगलवार, 7 जुलाई को इंडोनेशिया की संसद में संबोधन देते हुए कहा, मैं जहां-जहां गया, जिस किसी से मिला, हर चेहरे पर भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और आत्मीयता साफ दिखाई दे रही थी।

पीएम ने आगे भारत-इंडोनेशिया के रिश्तों को लेकर कहा, 'वैसे मैंने देखा कि यहां भारत का गाना कुछ-कुछ होता है, बहुत ही लोकप्रिय है। इस पर मैंने इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो से कहा, जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं, तब कुछ-कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है।'

पीएम नरेन्द्र मोदी को आज इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिंतांग रिपब्लिक इंडोनेशिया एडिपुर्णा' (बीतांग आदिपूर्णा) से सम्मानित किया गया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने जकार्ता के मेडेर्का पैलेस में आयोजित विशेष समारोह में यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया।

पीएम मोदी को मिला यह सम्मान इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो देश की एकता, निरंतरता और समृद्धि के लिए असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों

को दिया जाता है।

राष्ट्रपति प्राबोवो ने मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत-इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग बढ़ाने में उनके योगदान को यह सम्मान समर्पित है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को भारत के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित करते हुए कहा, 'यह सम्मान भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरी दोस्ती और साझा मूल्यों का प्रतीक है।'

पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच आर्थिक, रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त 35वां विदेशी नागरिक सम्मान है।

राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा- उनमें भारत का डीएनए, पीएम मोदी बोले- आप ने भारतीयों के दिलों को छू लिया

(जीएनएस)।

जकार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया और भारत-इंडोनेशिया के रिश्तों का प्रकाश डाला है. उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यताओं का रिश्ता है. साम्राज्य बने और गिरे, और दुनिया की राजनीति बदली, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच यह हमेशा रहने वाला रिश्ता बना रहा. यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है.

पीएम मोदी ने कहा, "राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने कहा था कि उनमें भारत का डीएनए है. आपके इस वाक्य ने भारतीयों के दिलों को छू लिया. ये डीएनए आपसी विश्वास से बना है, साझी विरासत से बना है, साझा स्मृतियों से बना है. भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है. इंडोनेशिया हो या भारत... हम दोनों ही देश विकास के लिए अधीर हैं. हमारे पास न रूकने का मौका है, न थमने का."

उन्होंने कहा, "यहां मैं जहां-जहां गया, जिस किसी से मिला, हर चेहरे पर भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और आत्मीयता स्पष्ट रूप से दिखाई दी. मैंने देखा कि यहां भारत का गाना 'कुछ कुछ होता है...' बहुत ही लोकप्रिय है. आज मैंने राष्ट्रपति प्रबोवो से इस पर कहा कि जब भारत-इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है. आज मुझे सुबह ही

इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला. इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान... ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है. ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है.

पीएम मोदी ने कहा कि चाहे महानदी पर केले की छाल से बनी छोटी नावों को तैराने की परंपरा हो, वायांग कुलित के जरिये महाभारत का मंचन हो, या देवी श्री की पूजा हो, हर परंपरा भारत और इंडोनेशिया के बीच हमेशा रहने वाले सांस्कृतिक संबंध को दिखाती है. इस रिश्ते का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही समृद्ध भी है.

उन्होंने कहा कि आज कल दुनिया में फुटबॉल फीवर (फुटबॉल खेल के प्रति दीवानगी) चल रहा है. यहां इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है. आप सभी वो ऊर्जा, वो जोश... यहां भी लेकर आए हैं, और दिखाई दे रहा है. एक अजब संयोग बना है कि जब भी मैं इंडोनेशिया आया हूं, फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है. लेकिन इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग मैन ऑफ द मैच हैं. आज का ये आयोजन भव्य भारत की जीती-जागती तस्वीर बने हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत की अर्थव्यवस्था... दुनिया के विकास को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रही है. जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी. जब पश्चिम एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था थमी नहीं.

उन्होंने आगे कहा, "ये गति, ये प्रगति... ऐसे ही नहीं आई है. भारत ने एक के बाद एक सुधार किए हैं, हमने लगातार काम किया है... इसलिए आज देश में बदलाव हो रहा है. रिफॉर्म्स, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म... इस मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं. भारत के विकास में जो स्पीड और स्केल है... उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा... 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं और सपने गतिमान हैं."

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में एक और ऐसी व्यवस्था बनी है जो अभूतपूर्व है, शानदार है. ये है डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (उझळ). ये ऐसी फुलप्रूफ व्यवस्था है, जिसमें बिना लीकेज लाभार्थियों तक पूरा पैसा पहुंच जाता है. बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपये लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे जा चुके हैं. जब ऐसी व्यवस्था बनती है तो लोगों का भरोसा बढ़ता है.

उन्होंने कहा कि ऊर्जा से लेकर संपर्क और चिप निर्माण तक... भारत रुकने वाला नहीं है. आज का भारत सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा है, बल्कि हर मित्र देशों के सपनों के साथ है. भारत सबका साथ-सबका विकास के मंत्र पर चलता है.

पीएम मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की सूची में एक और प्रतिष्ठित सम्मान जुड़ गया है। इंडोनेशिया ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' से सम्मानित किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को मिले वैश्विक सम्मानों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। बिंतांग आदिपूर्णा, जिसे 'मेडल ऑफ ऑनर' भी कहा जाता है, इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की एकता, निरंतरता और समृद्धि के लिए असाधारण योगदान दिया हो।

'मौन धारण किया है, एसआईटी रिपोर्ट के बाद, सच बताउंगा',चंपत राय ने तोड़ी चुप्पी, राम मंदिर चंदा चोरी पर कही ये बात

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से हटने वाले चंपत राय ने पहली बार इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है। पद छोड़ने के ठीक एक दिन बाद मंगलवार 7 जुलाई को उन्होंने राम भक्तों के नाम हाथ से लिखा एक भावुक पत्र जारी किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म '' पर इस पत्र को शेयर करते हुए उन्होंने साफ कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्होंने मौन धारण किया है।

अखिलेश और टिन्नू यादव के रिश्तेदार होने का दावा निशिकांत दुबे को पड़ा भारी! लखनऊ-इटावा में होगी एफआईआर

निशिकांत दुबे के खिलाफ सपा के नेता हजरतगंज थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाने वाले हैं. निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच रिश्ते होने का दावा किया था.

(जीएनएस)।

राम मंदिर चंदा चोरी मामला सामने आने के बाद से समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं. अखिलेश यादव ने ही सबसे पहले राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का सनसनीखेज दावा किया था, जिसके बाद जांच हुई और आरोप सही पाए गए. मामले में चंपत राय के पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम सामने आया था. अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच ही रिश्ते होने का दावा किया जिसके बाद से सियासी पारा हाई हो गया.

निशिकांत दुबे अपने इस दावे के

बाद से मुश्किल में आ गए हैं. टिन्नू यादव और अखिलेश यादव को रिश्तेदार बताने के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता निशिकांत दुबे से खासा नाराज हैं. इसी को लेकर सपा नेता मनोज काका एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंच गए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत के दावे किए गए हैं.

दूसरी तहरीर इटावा में दर्ज कराई गई है. समाजवादी पार्टी नेताओं ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे समेत पांच लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला है. समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल यादव समेत करीब दो दर्जन नगरपालिका सभासद, सपा नेता और कार्यकर्ता देर रात थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचे. सपा नेताओं का आरोप है कि अयोध्या राम मंदिर में कथित चोरी के मामले को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट प्रसारित की गई. इसी मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को शिकायत सौंपी गई.

हरित ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने के लिए बिहार ने केंद्र से मांगा सहयोग

(जीएनएस)।

बिहार राज्य में सौर अपनाने, ग्रिड एकीकरण और हरित हाइड्रोजन नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3305 टह हरित ऊर्जा गलियारे, इएर तैनाती, पीएम सूर्य होम विस्तार, और पीएम-कुसुम चरण कक्क को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय सहयोग का आग्रह करता है।

बिहार सरकार ने राज्य में हरित और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं ऊर्जा सचिव अजय यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (टटफए) के सचिव संतोष कुमार सारंगी से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की।

बैठक में बिहार में 3305 मेगावाट क्षमता के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के विकास के लिए आवश्यक स्वीकृति और वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना राज्य में प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की सुगम निकासी और ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। यह अवसंरचना जमुई, बांका, लखीसराय, औरंगाबाद और कैमूर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संभावित जिलों में स्थापित की जा रही सौर और इएर परियोजनाओं के प्रभावी संचालन में अहम भूमिका निभाएगी।

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार में योजना के विस्तार पर भी चर्चा हुई। राज्य में करीब 58 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ता हैं, जबकि फिलहाल केवल 2.5 लाख उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की स्वीकृति मिली है। राज्य सरकार ने पहले चरण में 10 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को योजना में शामिल करने का प्रस्ताव एमएनआरई को भेजा है। बिहार सरकार ने इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया।

बैठक में पीएम-कुसुम योजना (फेज-कक्क) के तहत 1000 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन, औरंगाबाद में 150 मेगावाट क्षमता के एएउक सोलर पार्क, बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) के क्षेत्रीय परिसर की स्थापना जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

वहीं ऊर्जा सचिव अजय यादव ने कहा कि इन परियोजनाओं के लागू होने से बिहार की ऊर्जा अवसंरचना और मजबूत होगी, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों के साथ आम उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और एमएनआरई सचिव संतोष कुमार सारंगी ने बिहार सरकार के प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करने और आवश्यक सहयोग देने का भरोसा दिलाया।

पाकिस्तान से तनातनी के बीच अचानक भारत पहुंचे अफगानिस्तान के मंत्री, बढ़ी हलचल

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। पाकिस्तान से तनातनी के बीच अफगानिस्तान के एक मंत्री अचानक भारत पहुंच गए हैं। भारत हमेशा से अफगानिस्तान का मददगार रहा है। इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी पोस्ट किया है। अफगानिस्तान के मंत्री की गर्मजोशी के साथ स्वागत की विदेश मंत्रालय ने एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर अफगानिस्तान के मंत्री के नई दिल्ली पहुंचने की जानकारी दी। उन्होंने एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा-अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी के नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया।'

रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा-'आपसी हित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद है।' हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़पें हुई थीं, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था।

भारत-अफगानिस्तान में आपसी हित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद है। -रणधीर जायसवाल, प्रवक्ता, भारतीय विदेश मंत्रालय

करीब तीन हफ्ते पहले ही भारत ने अफगानिस्तान को 5 टन जरूरी दवाओं की खेप भेजी थी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि यह मदद अफगानिस्तान के लोगों की सेहत और भलाई के लिए भारत की लगातार मानवीय प्रतिबद्धता को दिखाती है। भारत अपनी जारी मानवीय सहायता कोशिशों के तहत दवाओं, टीकों और राहत के अन्य सामानों के जरिए अफगानिस्तान की लगातार मदद करता रहा है।

जज रवि कुमार दिवाकर जिन्होंने 3 महीनों में 13 दोषियों को सुनाई मृत्युदंड

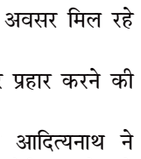

यूपी के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर एक बार फिर अपने कड़क फैसले को लेकर सुर्खियों में हैं। मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में तैनात जज रवि दिवाकर ने महज तीन महीनों के भीतर गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार कड़े फैसले सुनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बीते 6 अप्रैल से 6 जुलाई 2026 के बीच हुए जघन्य हत्याकांडों के 13 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मुज्जफरनगर में महज तीन महीने के दौरान अलग-अलग मामलों में 13 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक और सामाजिक हलकों में एक नई चर्चा छिड़ गई है।

₹384 करोड़ की योजनाओं की सौगात के साथ सीएम योगी का विपक्ष पर करारा प्रहार, कहा- हिंदू धर्म को बदनाम करने की रच रहे साजिश

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीएम ने साफ कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा.

(जीएनएस)।

प्रतापगढ़ः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जीआईसी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम से सदर और विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्रों के लिए 384 करोड़ रुपये की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी. साथ ही, उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश लूट और भ्रष्टाचार की चपेट में था, जबकि वर्तमान सरकार विकास, सुशासन और मजबूत कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है. वहीं, राम मंदिर में हुई चोरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष इस मामले को लेकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, जबकि घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. जांच निष्पक्ष होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. सीएम ने साफ कहा कि इस मामले में दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा. कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

भर्तियों में युवाओं को मिल रहा निष्पक्ष अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास और सुशासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई पुलिस की 60 हजार भर्तियों में प्रतापगढ़ के युवाओं को भी अवसर मिला है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में भी यहां के युवा सफलता प्राप्त कर रहे हैं. सीएम ने आरोप लगाया कि पहले सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता नहीं थी और योग्य युवाओं को अवसरों से वंचित होना पड़ता था, जबकि वर्तमान सरकार में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे प्रतिभाशाली युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिल रहे हैं.

सनातन धर्म पर प्रहार करने की हो रही कोशिश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से सनातन धर्म पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है. सपा और कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं. एक समय ऐसा था जब रामभक्तों पर गोलियां चलाई जाती थीं और भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे. यहां तक की "जय श्रीराम" का उद्घोष करने वालों पर पहले लाठी और गोली चलती थी,

लखनऊ के कई प्राइवेट पीजी और हॉस्टल बन गए हैं मनमानी का अड्डा

पढ़ाई और करियर के सपनों संग हर साल हजारों यंगस्टर्स राजधानी आते हैं। उनका पहला स्ट्रगल पीजी, हॉस्टल या रेंटल रूम ढूंढना होता है। बाहर से सुविधाओं और सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करने वाले कई प्राइवेट पीजी और हॉस्टल अंदर से मनमानी का अड्डा बने हुए हैं।

(जीएनएस)।

लखनऊ । पढ़ाई और करियर के सपनों संग हर साल हजारों यंगस्टर्स राजधानी आते हैं। उनका पहला स्ट्रगल पीजी, हॉस्टल या रेंटल रूम ढूंढना होता है। बाहर से सुविधाओं और सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करने वाले कई प्राइवेट पीजी और हॉस्टल अंदर से मनमानी का अड्डा बने हुए हैं

इन पीजी, हॉस्टल या रेंटल रूम में बिना एग्रीमेंट के स्टूडेंट्स को रखा जाता है, फिर अचानक किराया बढ़ा दिया जाता है। सिक्योरिटी मनी महीनों तक रोक ली जाती है और मेंटेनेंस के नाम पर पैसे काट लिए जाते हैं। नियम हर दिन बदलते हैं और सवाल पूछने पर मेंटल प्रेशर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा निशाने पर वे यंगस्टर्स रहते हैं जो नए शहर में अकेले और मजबूर होते हैं।

लखनऊ में सीतापुर, बलिया, गोंडा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों से बच्चे पढ़ने आते हैं और पीजी, हॉस्टल में रहते हैं। शहर भर में करीब 8 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर प्राइवेट पीजी और हॉस्टल्स का मकड़जाल फैला हुआ है। इन 8 जगहों पर ही 1000 से ज्यादा प्राइवेट पीजी और हॉस्टल चल रहे हैं। इनकी फीस 6000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक है और स्टूडेंट के बजट के हिसाब से सुविधाओं का लालच देकर ओनर्स पेरेंट्स को लूटते हैं।

राजधानी में स्टूडेंट्स के लिए सरकारी हॉस्टल कम हैं। वर्किंग वीमेन्स के लिए हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं। इनका फायदा प्राइवेट हॉस्टल्स और पीजी चलाने वाले उठा रहे हैं। इनका रेट भी किराएदार के प्रोफेशन के हिसाब से रहता है। स्टूडेंट्स के लिए रेंट अलग है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अलग और जॉब के हिसाब से रेंट बदलता रहता है।

पैसा तो कैश में चाहिए

पीजी ओनर हो या हॉस्टल मालिक, स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स को रखते टाइम उनका पहला एजेंडा पैसा होता है और बैकग्राउंड के हिसाब से वे हर किसी से अलग-अलग चार्ज करते हैं। सबसे शॉकिंग बात है कि ओनर पैसा कैश मे मांगते हैं क्योंकि ऑनलाइन पैसे पे करने पर प्रूफ रहता है कि पर्सन ने कितना पैसा दिया है, लेकिन कैश में ओनर अपने हिसाब से पैसे ले लेता है।

दो माह की सिक्योरिटी मनी

जिसमें रेंट के अलावा 1-2 महीने की सिक्योरिटी मनी भी शामिल रहती है। अगर गर्ल्स पीजी का मंथली रेंट 12 हजार है तो कम से कम 1 महीने की सिक्योरिटी भी जमा करनी होती है, जिसमें टेनेंट को 24,000 रुपए कैश में पहले देने होंगे।

हड़प लेते हैं सिक्योरिटी मनी

अलीगंज में ब्वॉयज हॉस्टल में रहने वाले हर्षित ने बताया कि पीजी में शिफ्टिंग के टाइम रेंट और सिक्योरिटी मिलाकर मैंने 16,000 रुपए दिए थे। जिसमें 8 हजार रेंट और 8 हजार सिक्योरिटी मनी थी। सात महीने रहने के बाद जब मैंने पीजी चेंज किया तो ओनर ने पहले तो सिक्योरिटी मनी वापस करने से मना कर दिया। जब मैंने कई लोगों से उनकी बात करवाई तब जाकर उन्होंने 5,000 रुपए वापस किए और 3,000 अपने पास यह कहते हुए रख लिए कि उन्हें मेंटिनेंस कराना पड़ेगा, जिसमें खर्चा होता है।

1-हमने जब अपार्टमेंट लिया था तो एक साल का अग्रीमेंट था। जिसमें शेयरिंग की कोई शर्त नहीं थी, लेकिन ओनर ने बीच में ही एक शर्त रख दी कि दो से ज्यादा लोग शेयरिंग में नहीं रहेंगे जबकि स्पेस भी है।

-शिवि

2-हॉस्टल में रहने के टाइम स्टार्टिंग में तो ओनर कहते हैं कि सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन अब न तो लाइट प्रॉपर आती है न ही बाकी फैसिलिटीज हैं। बस पैसा लिया जा रहा है।

-हर्ष श्रीवास्तव

3-दूसरे शहर में पीजी, हॉस्टल में रहना आसान नहीं है। फ्रीडम नहीं मिलती है और हॉस्टल के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल बनाना पड़ता है। सीमित सुविधाओं और घर से दूर रहने पर इमोशनल सपोर्ट भी कम मिलता है।

-इनीशिका शर्मा

4-हॉस्टल में रेंट के साथ सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। जब हॉस्टल खाली करो तो ओनर सिक्योरिटी मनी वापस करने में आनाकानी करते हैं। अच्छा खासा अमाउंट काटकर ही वापस करते हैं।

- नवनीत श्रीवास्तव

बिहार से दिल्ली तक एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, कंबोडिया नौकरी रैकेट पर एक्शन

(जीएनएस)।

कंबोडिया में भारतीय युवाओं को नौकरी का झांसा देकर फंसाने वाले मानव तस्करी और साइबर गुलामी रैकेट के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुल छह ठिकानों पर छापेमारी की। बिहार के गोपालगंज, सीवान, सारण और पूर्वी चंपारण में भी तलाशी ली गई।

इस दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल उपकरण और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। जांच में सामने आया है कि युवाओं को अच्छी नौकरी का लालच देकर कंबोडिया भेजा जाता था, जहां उन्हें जबरन ऑनलाइन ठगी करने वाली कंपनियों में काम कराया जाता था।

बिहार समेत तीन राज्यों में NIA की छापेमारी

NIA ने इस मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के छह अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बिहार के गोपालगंज, सीवान, सारण और पूर्वी चंपारण जिले कार्रवाई के केंद्र रहे। जांच एजेंसी ने बताया कि ये ठिकाने गिरफ्तार आरोपियों और फरार लोगों के सहयोगियों से जुड़े थे। तलाशी के दौरान कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। इनके जरिए एजेंसी पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।

नौकरी का झांसा देकर युवाओं को भेजा जाता था कंबोडिया

जांच में पता चला है कि गिरोह भारत के बेरोजगार और जरूरतमंद युवाओं को विदेश में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का लालच देता था। इसके लिए अलग-अलग राज्यों में एजेंट और ट्रैवल एजेंटों का इस्तेमाल किया जाता था। जब युवक कंबोडिया पहुंचते थे, तो उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते थे और उन्हें ऐसी कंपनियों के हवाले कर दिया जाता था जो ऑनलाइन ठगी का काम करती थीं। इस तरह युवाओं को धोखे से साइबर अपराध के जाल में फंसा दिया जाता था।

मना करने पर दी जाती थी अमानवीय यातना

पीड़ितों ने ठक्अ को बताया कि कंबोडिया पहुंचने के बाद उन्हें जबरन साइबर फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया जाता था। यदि कोई काम करने से इनकार करता था तो उसके साथ मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया जाता था। कई लोगों को बिजली के झटके दिए गए, कमरे में बंद रखा गया और खाना-पानी तक नहीं दिया गया। पीड़ितों के मुताबिक उन्हें लगातार डराकर रखा जाता था ताकि वे भाग न सकें और मजबूरी में गिरोह के लिए काम करते रहें।

मास्टरमाइंड आनंद कुमार सिंह अब भी फरार

इस पूरे गिरोह का मुख्य आरोपी आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह बताया गया है, जो अभी भी फरार है। ठक्अ ने मई 2026 में उसके साथ प्रह्लाद कुमार सिंह, अभय नाथ दुबे, अभिरंजन कुमार और रोहित यादव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इससे पहले फरवरी 2026 में अभय, अभिरंजन और रोहित को कंबोडिया से लौटने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।

पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी NIA

NIA अब इस मानव तस्करी और साइबर अपराध से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। जब्त किए गए मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी ताकि देश और विदेश में फैले इस गिरोह के बाकी सदस्यों की पहचान हो सके। एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि अब तक कितने भारतीय युवाओं को इस तरीके से कंबोडिया भेजा गया और इस रैकेट में कौन-कौन लोग शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे भी जारी रहेगी।

'विकसित भारत कॉन्क्लेव' में शिशिर बजाज को मिला 'महाराष्ट्र का गौरव' का प्रतिष्ठित सम्मान

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अन्य अति विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में इंडस्ट्री, सर्विस और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में बजाज समूह के 100 वर्षीय योगदान का हुआ सम्मान

मुंबई, 7 जुलाई। देश की राजधानी नई दिल्ली के हयात रीजेंसी में हुए एक भव्य समारोह में, बहुचर्चित कॉफी टेबल बुक ह्यमहाराष्ट्र के गौरवह्न का विमोचन सम्पन्न हुआ। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, अन्य सीनियर कैबिनेट मंत्री, पॉलिसी बनाने वाले इंडस्ट्रियल लीडर और देश भर से आये खास मेहमान मौजूद थे। इस स्पेशल एडिशन में शामिल जानी-मानी हस्तियों में बजाज ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस और बजाज फाउंडेशन के अध्यक्ष शिशिर बजाज भी शामिल हैं। उनके जीवन और योगदान को नौ पृष्ठों के एक विशेष फीचर में दशार्या गया है। इसमें बजाज समूह के फाउंडर, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, इंडस्ट्रियल पायनियर और महात्मा गांधी द्वारा दत्तक लिये गये पॉंचवें बेटे श्री जमनालाल बजाज के विजन को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका पर रोशनी डाली गई है।

इस गरिमापूर्ण समारोह में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा श्री शिशिर बजाज को भारतीय इंडस्ट्री, खासकर चीनी और इथेनॉल सेक्टर में उनके शानदार योगदान और ग्रामीण विकास और सामाजिक बदलाव के लिए उनकी ज़िंदगी भर की लगन के लिए "महाराष्ट्र का गौरव" के प्रतिष्ठित अलंकरण से सम्मानित किया गया। यह पहचान एक ऐतिहासिक मौके पर मिली है, जब बजाज परिवार अपनी एंटरप्राइज, राष्ट्र निर्माण और जन सेवा की हमेशा रहने वाली विरासत के 100 साल पूरे कर रहा है। राष्ट्र पहले, आत्म निर्भरता और सामाजिक ज़िम्मेदारी के सिद्धांतों पर बनी बजाज समूह की विरासत भारत की बदलती जरूरतों के साथ लगातार बदली है। जहाँ श्री जमनालाल बजाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया और स्वदेशी एंटरप्राइज की नींव रखी, वहीं उनकी अगली पीढ़ियों ने उन आदर्शों को ऐसे संस्थानों में बदल दिया, जो पूरे देश में आर्थिक और सामाजिक मूल्यों की स्थापना निरंतर जारी रखे हुए हैं। श्री शिशिर बजाज की लीडरशिप में,

बजाज फाउंडेशन के चेयरमैन शिशिर बजाज, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल से महाराष्ट्र के गौरव का प्रतिष्ठित सम्मान ग्रहण करते हुए। दूसरे फोटो में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कॉफी टेबल बुक के विमोचन का दृश्य और तीसरे चित्र में श्री शिशिर बजाज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अन्य अतिथियों से बातचीत करते हुए।

बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड चीनी और इथेनॉल प्रोड्यूसर में से एक बनकर उभरी, जिसने देश के बायोफ्यूल इकोसिस्टम को मजबूत करने और भारत के एनर्जी सिक्योरिटी लक्ष्यों को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल के दौरान, कम्पनी दो चीनी मिलों से बढ़कर चौदह चीनी मिलों और एक डिस्टिलरी से छह डिस्टिलरी तक पहुँच गई, जिससे यह भारत की चीनी और इथेनॉल इंडस्ट्री में एक लीडिंग ताकत बन गई। श्री शिशिर बजाज ने ग्रुप के बिजनेस इंटरेस्ट को चीनी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से आगे एनर्जी सेक्टर में डायवर्सिफाई करने में भी अहम भूमिका निभाई। वर्तमान में, उनके बड़े सुपुत्र और बजाज ग्रुप के चेयरमैन श्री कुशाग्र बजाज की लीडरशिप में, बजाज ग्रुप चीनी, इथेनॉल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और पावर जेनरेशन में अपने इंटरेस्ट के जरिये इस मजबूत नींव पर उल्लेखनीय काम कर रहा है। बजाज एनर्जी लिमिटेड और ललितपुर पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के जरिये, बजाज ग्रुप ने 2430 टह की थर्मल पावर जेनरेशन कैपेसिटी के साथ भारत के पावर सेक्टर में एक अहम मौजूदगी बनाई है और उत्तर प्रदेश की बिजली की जरूरतों में यह समूह महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत की लम्बे समय की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के अपने कमिटमेंट को जारी रखते हुए, बजाज ग्रुप कुशल, सस्टेनेबल और स्ट्रेटेजिक एनर्जी सॉल्यूशंस के जरिए देश के भविष्य में योगदान देने के लिए टेक्नोलॉजी की निरंतर खोज कर रहा है। कॉफी टेबल बुक के विशेष फीचर में बजाज फाउंडेशन और श्री शिशिर बजाज की देखरेख में जुड़े ट्रस्टों के जरिये हुए शानदार सामाजिक प्रभाव को भी बखूबी दशार्या गया है। वर्धा (महाराष्ट्र), सीकर (राजस्थान) और ललितपुर (उत्तर प्रदेश) में, पानी बचाने, नदियों को फिर से ज़िंदा करने, नेचरल खेती, महिलाओं को मजबूत बनाने, रिन्यूएबल एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट और गॉंवों में रोजगार के लिए फाउंडेशन की उल्लेखनीय कोशिशों ने 2,000 से ज्यादा गॉंवों में 22 लाख से ज्यादा लोगों की ज़िंदगी पर अच्छा असर डाला है। इस विशेष में श्री शिशिर बजाज के छोटे सुपुत्र श्री अपूर्व नयन बजाज के योगदान को भी दिखाया गया है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर विकास की कोशिशों के जरिये परिवार के जन-हितकारी कामों को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। विशेष फीचर में बजाज परिवार की पॉंचवीं पीढ़ी के उभरने के बारे में भी बताया गया है, जिसे सुश्री आनंदमयी बजाज रिप्रेजेंट करती हैं। उन्होंने हाल ही में ग्रुप में जनरल मैनेजर झ्र ग्रुप स्ट्रैटेजी के तौर पर अपना दायित्व ग्रहण किया है और ज़िम्मेदार लीडरशिप के लिए परिवार के सदियों पुराने कमिटमेंट को आगे बढ़ा रही हैं। हाल ही में, श्री शिशिर बजाज को इंडस्ट्री, ग्रामीण विकास और सामाजिक -आर्थिक बदलाव में उनके योगदान के लिए महाराष्ट्र के माननीय गवर्नर द्वारा प्रतिष्ठित सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भी दिया गया था। कॉन्क्लेव में जानी-मानी हस्तियों ने बजाज परिवार की इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस को सोशल कमिटमेंट के साथ जोड़ने की अनोखी काबिलियत को माना, जिससे यह भारत के सबसे सम्मानित बिजनेस परिवारों में से एक बन गया है। जैसे- जैसे भारत विकसित भारत- 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, श्री शिशिर बजाज और बजाज परिवार की कहानी इस बात का एक मजबूत उदाहरण है कि कैसे एंटरप्राइज, सोशल ज़िम्मेदारी और राष्ट्रीय मकसद मिलकर लम्बे समय तक चलने वाला असर डाल सकते हैं। श्री शिशिर बजाज और बजाज परिवार पर पूरे 9 पृष्ठों का फीचर इस लिंक के जरिये पढ़ा जा सकता है :- PDF लिंकः https:// bajajgroup.org/ bajajgroup_assets/ s3fs-public/documents/ Navabharat_ Articles.pdf

भारत आ रहे गैस टैंकर पर होर्मुज में भयंकर ड्रोन अटैक, 29 क्रू मेंबर थे सवार

(जीएनएस)।

भारत आ रहे एलएनजी जहाज पर संदिग्ध ड्रोन हमले की खबर ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। 7 जुलाई 2026 को ओमान की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अछ फएडअ अळ नामक एलएनजी कैरियर कथित तौर पर ड्रोन हमले का शिकार हुआ। शुरूआती जानकारी के अनुसार हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई और भारी धुआं फैल गया। हालांकि चालक दल ने समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया।

राहत की बात यह है कि जहाज पर सवार सभी 29 क्रू सदस्य, जिनमें चार भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, सुरक्षित हैं। यह जहाज कतर के रास लाफान से गुजरात के दहेज बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास हुआ संदिग्ध हमला

यह घटना ओमान की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के निकट हुई, जो दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। इसी रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और एलएनजी की वैश्विक आपूर्ति होती है। ऐसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में किसी भी तरह के ड्रोन हमले की आशंका अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मानी जा रही है। फिलहाल संबंधित एजेंसियां घटना की परिस्थितियों और हमले के कारणों की जांच कर रही हैं।

इंजन रूम में लगी आग, लेकिन सभी चालक दल सुरक्षित

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संदिग्ध ड्रोन के टकराने के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई, जिससे भारी धुआं उठने लगा। चालक दल ने तुरंत आपातकालीन सुरक्षा प्रक्रियाएं लागू कीं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में किसी भी चालक दल के सदस्य को चोट नहीं आई। जहाज पर मौजूद सभी 29 नाविक सुरक्षित हैं, जिनमें चार भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। पर्यावरण को किसी प्रकार के नुकसान की भी फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है।

कतर से गुजरात के दहेज आ रहा था एलएनजी जहाज

एलएनजी कैरियर अछ फएडअ अळ कतर के प्रमुख गैस निर्यात केंद्र रास लाफान से तरलीकृत प्राकृतिक गैस लेकर भारत के गुजरात स्थित दहेज बंदरगाह की ओर जा रहा था। घटना के बावजूद जहाज ने अपनी यात्रा जारी रखी है और उसे दहेज पहुंचने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत के लिए एलएनजी की आपूर्ति ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इस जहाज से जुड़ी घटना पर भारतीय एजेंसियां भी लगातार नजर बनाए हुए हैं।

टूटने वाला है नेटो? अंकारा समिट में खींचतान, क्या है ट्रंप का अल्टीमेटम जिससे बढ़े मतभेद?

(जीएनएस)।

तुर्किए की राजधानी अंकारा में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन एक ऐसे मोड़ पर शुरू हुआ है, जहां पूरे यूरोप की सुरक्षा और भू-राजनीति दांव पर लगी है। यह हाई-प्रोफाइल बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सदस्य देशों पर रक्षा बजट बढ़ाने के अभूतपूर्व दबाव के बीच हो रही है। दूसरी तरफ, अमेरिकी तेवरों से चिंतित यूरोपीय देश नए सैन्य समझौतों की घोषणा कर ट्रंप को शांत करने की रणनीति बना रहे हें। कहा ये भी जा रहा है कि ट्रंप के दबाव के चलते ये संगठन अपना भरोसा और मजबूती खोता जा रहा है।

इस कूटनीतिक रस्साकशी का बैकग्राउंड पिछले साल हेग में तैयार हुआ था, जहां नाटो देशों ने अपनी GDP का 5 प्रतिशत डिफेंस और सिक्योरिटी पर खर्च करने का टारगेट रखा था। इस मास्टर प्लान के तहत साल 2035 तक मूल रक्षा बजट को 3.5% और सुरक्षा आवश्यकताओं को 1.5% तक पहुंचाना है। अंकारा में इस समय इसी कड़े रोड़मैप को जमीन पर उतारने को लेकर माथापच्ची चल रही है।

गैर NATO देशों की ज्यादा बड़ी डिमांड

इस सम्मेलन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इसमें नाटो के सभी 32 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा कई गैर-आधिकारिक देशों के प्रभावशाली नेता भी पहुंचे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की मौजूदगी ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा है। इनके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों के रक्षा और विदेश मंत्री भी अंकारा में डेरा डाले हुए हं। जेलेंस्की इस मंच का इस्तेमाल सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम (ढं३१ङ्ग३ अ१ ऊील्लरी र८२३ी२) की मांग के लिए करने जा रहे हैं। कीव में हाल ही में हुए रूसी ड्रोन हमलों में 11 नागरिकों की मौत के बाद यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम गहरे दबाव में है।

सीरियाई राष्ट्रपति- अंकारा में हैं पर समिट में नहीं

इसी बीच, सीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अहमद अल-शरा भी अंकारा पहुंचे हैं। हालांकि वे आधिकारिक तौर पर समिट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन राजनयिक गलियारों में चर्चा है कि ट्रंप के साथ होने वाली उनकी द्विपक्षीय मुलाकात पश्चिम एशिया के समीकरण बदल सकती हे।

ट्रंप का 'नो फ्री राइड' अल्टीमेटम और तुर्किए का नया रसूख

डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही नाटो के अस्तित्व और उसमें अमेरिका के भारी वित्तीय योगदान पर सवाल उठाते रहे हैं।

उनका तर्क है कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसे पर यूरोपीय देश "मुफ्त की सुरक्षा" का आनंद ले रहे हैं। ट्रंप ने जर्मनी के मौजूदा रक्षा बजट को 'हास्यास्पद' तक करार दिया, जिस पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी बेहद कड़ा रूख अपनाया है।

एक दिलचस्प कूटनीतिक पहलूः ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर उनके विश्वसनीय सहयोगी और तुर्किए के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन इस समिट के होस्ट न होते, तो शायद वे इस बैठक से दूरी बना लेते। हाल के वर्षों में तुर्किए ने न केवल अपने रक्षा बजट को सुधारा है, बलकि वह नाटो के भीतर एक प्रमुख हथियार सप्लाई करने वाले देश बनकर उभरा है। यही वजह है कि यह समिट तुर्किए को पश्चिम और मध्य-पूर्व के बीच एक मजबूत मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर रही है।

अमेरिकी सेना की वापसी का डर बनाम जमीनी हकीकत

इस खींचतान के बीच वाशिंगटन ने यूरोपीय देशों पर दबाव दोगुना करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने यूरोपीय क्षेत्रों से अपने फाइटर जेट्स, नेवल वॉरशिप और सबमरीनों को एक सीक्वेंस में वापस बुलाने का फैसला किया है। जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिकन एयरफोर्स और नेवी की इस आंशिक वापसी से यूरोप का सुरक्षा संतुलन तात्कालिक रूप से डगमगा सकता हे।

हालांकि, रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बजट को कागज पर बढ़ाना और उसे वास्तविक सैन्य ताकत में तब्दील करना कोई आसान काम नहीं है। यदि यूरोपीय देश आज बड़े पैमाने पर नए रक्षा सौदे करते भी हैं, तो नए हथियारों की डिलीवरी होने और सैनिकों को उनके संचालन की ट्रेनिग देने में कई साल लग जाएंगे। इसलिए, बजट में इस अचानक बढ़ोतरी का ग्राउंड रियलिटी पर तुरंत कोई जादुई असर दिखना मुश्किल है।

टिकेगा या टूटेगा ठअळड?

अंकारा का यह शिखर सम्मेलन भले ही जमीन पर तुरंत कोई बड़ा सैन्य बदलाव न ला पाए, लेकिन इसका राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश बेहद गहरा है। रक्षा बजट और खर्चों को लेकर जारी इस तीखी जुबानी जंग के बावजूद, नाटो के सदस्य देश दुनिया के सामने अपनी सामूहिक एकजुटता (वल्लर३ी ऋ१ङ्गल्ल३) प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वैश्विक संकट के दौर में अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपसी दरारों को छिपाकर एकजुट दिखना ही इस पूरी बैठक का तात्कालिक और सबसे बड़ा लक्ष्य है। ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि ठअळड टूट रहा है लेकिन ये जरूर है कि इसमें मौजूद सदस्यों में मतभेद बढ़ रहे हैं।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

सीरिया को अस्थिर करने के लिये दमिश्क में विस्फोट

दमिश्क विस्फोट मंगलवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो धमाका हुआ, वह उस होटल फोर सीजन्स के नजदीक हुआ जिसमें प्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ठहरे हुए थे। वे दमिश्क के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात के लिए उनके सरकारी निवास पर गए हुए थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उनके देश के व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी था। इस हमले में मरा तो कोई नहीं किन्तु सुरक्षाकर्मियों सहित 18 लोग घायल हुए। राष्ट्रपति मैक्रों ने तुका की राजधानी अंकारा से पहले दमिश्क की यात्रा की योजना बनाई थी। अंकारा में बुधवार से नाटो शिखर सम्मेलन की बैठक होनी है और उसमें प्रांस के राष्ट्रपति को शामिल होना था। दरअसल अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस विस्फोट के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि जिन लोगों ने इस विस्फोट की साजिश की है, या तो वे सीरिया को अस्थिर करने वाले लोग हैं अथवा प्रांस के सक्रिय इस्लामिक आतंकी संगठन के लोग हैं। किन्तु इतना तो तय है कि इस घटना से एक बात तो बिलवुल साफ हो गई है कि राष्ट्रपति मैक्रों की सुरक्षा जितनी पुष्ट होनी चाहिए थी, उतनी की नहीं गई। राष्ट्रपति मैक्रों अपने देश में तो इस्लामिक आतंक से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और काफी हद तक इन संगठनों पर नियंत्रण भी हासिल कर लिया है लेकिन दमिश्क में घटना स्थल की समीक्षा करने पर एक बात तो स्पष्ट होती है कि जो लोग राष्ट्रपति मैक्रों को निशाना बनाना चाहते थे, वे भी बड़ी आसानी से उस होटल तक पहुंच गए जिसमें प्रांस जैसे बड़े यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश ठहरा हुआ था। कल्पना कीजिए कि यदि राष्ट्रपति मैक्रों को वुछ हो जाता तो दुनिया में इसका क्या संदेश जाता। प्रांस के इस्लामिक कट्टरपंथी अपने प्रयास में सफल होने का जश्न मनाते ही साथ ही सत्ता विरोधी सीरिया की ताकतों को यह कहने का अवसर मिल जाता कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया। इस घटना से एक बात तो स्पष्ट है कि विश्व के वुछ देश जितना ध्यान अपने विरोधी देश को तबाह करने पर दे रहे हैं, यदि उतना ही वे आतंकवादियों को समाप्त करने पर देते तो शायद दुनिया का ज्यादा भला होता। हैरानी की बात तो यह है कि आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा तक नहीं तय कर सका। जब भी किसी आतंकी संगठन को यूएनओ प्रतिबंध लगाता है तो पी-5 यानि स्थायी सदस्य देश वीटो लगाकर उन्हें बचा लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आतंकी संगठन किसी देश के लिए आतंकी होते हैं, वहीं दूसरे देश के लिए वह स्वतंत्रता सेनानी बन जाते हैं। यही कारण है कि निन्दा तो आतंकवाद की सभी देश करते हैं किन्तु अपनी सुविधा के अनुसार ही। मतलब यह हुआ कि ले देकर आज दुनिया के पास फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) रह गई है जो आतंकियों पर नियंत्रण लगाने के लिए अस्तित्व में है। 1989 में जी-7 देशों ने एफएटीएफ संगठन का गठन किया था। किन्तु एफएटीएफ की निगरानी सूची में शामिल देशों को भी यदि ज्यादा सदस्य देश चाहें तो मिलकर वोटिंग के माध्यम से बाहर कर सकते हैं। बहरहाल विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद बना हुआ है। इसे खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक के लिए घातक और दूसरे के लिए अच्छा आतंकवाद अब और चलेगा। आतंकवाद विघटनकारी प्रवृत्ति है और इसे नष्ट करने के लिए हर देश को अपने तुच्छ स्वार्थ को त्यागना होगा, अन्यथा आज जैसे प्रांस के राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया। उसी तरह दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को भी बनाया जा सकता है।

बांकीपुर उप चुनावः प्रशांत किशोर की चुनौती, खोने को कुछ नहीं पीके के पास

(जीएनएस)।

बिहार में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से उप चुनाव लड़ने वाले हैं. रविवार को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है. बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से बीजेपी के नितिन नबीन जीते थे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने यह सीट छोड़ दी थी.

चुनाव आयोग ने बताया है कि मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट के साथ ही बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी.

प्रशांत किशोर का विधानसभा उप चुनाव लड़ने का फैसला कई मायनों में हैरान करने वाला भी है, क्योंकि बांकीपुर सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है और राज्य में उसके नेतृत्व में सरकार भी चल रही है.

ऐसे में प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, यह देखना भी दिलचस्प होगा.

इससे पहले, बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के दौरान उन्होंने अंतिम समय में खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया था. उन्होंने कहा था कि 'यह उनकी पार्टी का फैसला था कि राज्य की अन्य सीटों पर ध्यान देना जरूरी है.'

इसके बाद भी विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी का खाता नहीं खुला था.

बांकीपुर सीट की एक खास बात पर गौर करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कुल दस उम्मीदवार खड़े हुए थे और इनमें से सभी सामान्य (जनरल) वर्ग के थे.

बांकीपुर सीट से विधानसभा उप चुनाव लड़ने के पीछे प्रशांत किशोर की क्या रणनीति हो सकती है, यह सवाल कई लोगों के मन में उत्सुकता पैदा कर सकता है.

क्या बिहार की सियासत से नीतीश कुमार की विदाई और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशांत किशोर कोई नया सियासी समीकरण तलाशने की कोशिश में हैं.

प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के लोगों से कहा, "मोदी जी तो आपसे बात करने आएंगे नहीं. आज भी नहीं आएंगे, पांच बरस बाद भी नहीं आएंगे. कैसे मोदी जी को पता चलेगा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से आप खुश नहीं हैं. भाजपा को बांकीपुर से हराइए. उन तक अपने आप खबर पहुंच जाएगी कि उन्होंने जिस व्यक्ति का चुनाव किया है, उससे आप सहमत नहीं हैं."

वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण कहते हैं कि प्रशांत किशोर के पास चुनाव में हारने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सीट उन्हें हेडलाइन्स में जगह दिला सकती है.

वह कहते हैं, "ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. वो ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है. यहां से चुनाव लड़ते ही वो चर्चा में आ जाएंगे."

इस क्षेत्र से नितिन नबीन पांच बार चुनाव जीत चुके हैं, इससे पहले उनके पिताजी यहां से विधायक होते थे. पहले यह इलाका पटना पश्चिम विधानसभा सीट के अंतर्गत आता था.

नितिन नबीन ने साल 2006 में पहली बार इस सीट से चुनाव जीता था. उसके बाद बांकीपुर सीट बनने पर साल 2010 से नितिन नबीन ही लगातार यहां से बीजेपी के विधायक रहे.

बांकीपुर विधानसभा सीट पटना के शहरी क्षेत्र में आती है.

नचिकेता नारायण कहते हैं, "पीके जीत गए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी और कभी-कभी लोगों को लगता है कि वो हारकर भी सुर्खियाँ बटोर लेंगे, जैसे कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे."

"बांकीपुर सीट अब हाई-प्रोफाइल सीट बन गई है और यहां बीजेपी जो भी उम्मीदवार उतारेगी वह इलाके के लिए नया नाम होगा, जबकि पीके को लगता है कि उन्हें जनता कम-से-कम जानती तो है ही."

नचिकेता नारायण ने कहा, "प्रशांत किशोर के मन में अपना तलाश में हैं कि अगड़ी जाति के बीजेपी समर्थक सम्राट चौधरी को

मुख्यमंत्री बनाने या भोजपुर और कुछ अन्य घटनाओं की वजह से नाराज हैं. ऐसे में पीके को लगता है कि वोटर उन्हें वोट देकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से अपनी नाराजगी जता सकते हैं."

बिहार में भोजपुर ज़िले के भरत भूषण तिवारी के 'एनकाउंटर' का मामला पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्ख़ियों में है. 7 जून को पुलिस ने भरत तिवारी का 'एनकाउंटर' किया, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.

बीते कुछ समय में बिहार में हुई कई घटनाओं को लेकर प्रशांत किशोर काफी सक्रिय भी दिखे हैं.

बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से काफी कम वोटिंग के लिए जानी जाती रही है. पिछले साल हुए चुनाव में भी इस सीट पर करीब 41% वोट डाले गए थे.

यानी वोटरों के बीच जिस 'अर्बन अपैथी' (शहरी उदासीनता) की बात की जाती है, वह बांकीपुर के वोटर टर्न आउट में दिखती है.

बीजेपी को साल 2025 में यहां करीब 25% वोट मिले थे और नितिन नबीन ने करीब 52 हजार वोटों से जीत दर्ज की थी.

यानी बीजेपी को इस सीट पर करीब 75% वोटरों ने वोट नहीं दिया. जाहिर है प्रशांत किशोर इस गणित में अपने लिए संभावना की तलाश जरूर करेंगे, जो बीजेपी के सामने एक चुनौती हो सकती है.

बीजेपी के लिए यहां एक अन्य चुनौती यह भी हो सकती है कि जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है, उस पर न केवल वह जीत हासिल करे, बल्कि जीत के अंतर को भी बचा कर रखे. वरिष्ठ पत्रकार माधुरी कुमार कहती हैं, "मैं समझती हूं कि प्रशांत किशोर को लगता है कि कम से कम उनके खुद के मुकाबले बीजेपी के पास इस सीट पर कोई जाना-पहचाना चेहरा नहीं है, तो वो इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं."

वह कहती हैं, "प्रशांत किशोर किसी भी तरह बिहार की सियासत में एक एंट्री चाहते हैं. साल 2025 के विधानसभा चुनावों में उन्हें फीडबैक मिल गया था कि वो हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा. संभव है इस बार उन्हें कोई फीडबैक मिला हो कि उनके पास बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवारों के मुकाबले बढ़त है."

हालांकि साल 2025 के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो इस सीट पर जन सुराज पार्टी की वंदना कुमारी भले ही तीसरे नंबर पर थीं, लेकिन उन्हें 5% से भी कम वोट मिले थे.

जन सुराज का चुनावी प्रदर्शन

बांकीपुर की जनता से संवाद करते हुए प्रशांत किशोरइमेज स्रोत,@खअठरवफ्रअखडठछक्ष्ठए

इमेज कैप्शन,बांकीपुर की जनता से संवाद करते हुए प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने राजनीति में एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर एंट्री की थी. वो अक्सर दावा करते हैं कि उन्होंने कई सियासी दलों को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

उन्होंने बिहार में कई जगहों की यात्रा की और अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश भी की. फिर साल 2024 में उन्होंने अपनी जन सुराज पार्टी बनाई.

हालाँकि पहले उन्होंने खुद संभावना जताई थी कि वो राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. यह सीट आरजेडी की परंपरागत सीट रही है और साल 2025 में तेजस्वी यादव यहां से चुनाव लड़ रहे थे.

कई लोगों के मानना था कि चुनाव के ठीक पहले प्रशांत किशोर का चुनाव मैदान से पीछे हट जाना, पार्टी के बहुत बुरे प्रदर्शन के पीछे एक वजह थी.

उन चुनावों में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 89 पर सीटें बीजेपी के खाते में गईं, जबकि जेडीयू को 85 सीटें मिलीं. वहीं राष्ट्रीय जनता दल 25 और एलजेपी (आर) को 19 सीटों पर जीत मिली थी.

जन सुराज पार्टी चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी. पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि उसके 238 में से 236 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए.

उन चुनावों में प्रशांत किशोर की पार्टी को कुल करीब 3.4 फीसदी वोट मिले थे और वे जिन दावों के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे वो पूरी तरह धराशायी हो गए.

आमतौर पर उप चुनावों को लेकर वोटरों या राजनीतिक विश्लेषकों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखती है, लेकिन पीके ने उम्मीदवार बनने की घोषणा कर बांकीपुर सीट पर कई लोगों की नजर टिका दी है.

'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब

(जीएनएस)।

खबर आई कि चीनी सेना भारत की सीमा के भीतर 60 किलोमीटर तक घुस आई है. अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबांसरी जिले के तक्सिंग क्षेत्र में चीनी सेना 60 किलोमीटर अंदर घुसने और नए कैंप बनाने की खबरें सामने आई थीं. दावा इतना गंभीर है कि स्वाभाविक तौर पर लोगों के बीच चिंता और सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? सरकार ने इस दावे पर स्थिति साफ कर दी है. इस वायरल दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है. सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे वीडियो का भारत-चीन सीमा से कोई संबंध नहीं है. यानी जिस वीडियो को सीमा पर चीनी सेना की घुसपैठ बताकर फैलाया जा रहा है, वह भ्रामक है और गलत दावे के साथ प्रसारित किया जा रहा है.

PIB Fact Check ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, "यह दावा फर्जी है. सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे वीडियो भारत-चीन सीमा के नहीं हैं और इनका इस दावे से कोई संबंध नहीं है."

भारत-चीन सीमा से जुड़ी खबरें हमेशा संवेदनशील मानी जाती हैं. ऐसे में किसी भी अपुष्ट वीडियो या संदेश के वायरल होने से भ्रम फैल सकता है. यही वजह है कि सरकार ने लोगों से अपील की है कि सीमा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर केवल आधिकारिक और सत्यापित स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें.

फर्जी दावों के साथ वायरल होने वाले वीडियो और पोस्ट अक्सर पुराने, दूसरे देशों के या किसी अलग घटना के होते हैं, जिन्हें नए संदर्भ में पेश कर दिया जाता है. इससे न केवल लोगों में भ्रम पैदा होता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर गलत सूचना भी तेजी से फैलती है.

असली खबर क्या थी?

पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश से लगी भारत-तिब्बत सीमा पर चीन की ओर से नई सड़क बनाए जाने का खुलासा ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ था. यह सड़क उस विवादित क्षेत्र में दो बस्तियों को जोड़ती है, जो 1959 से चीन के नियंत्रण में है और वर्तमान में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पार स्थित है. नई सड़क 2021 में बसाए गए एक गांव को 2026 में विकसित की गई नई बस्ती से जोड़ती है. इन बस्तियों में हेलिपैड और सीमेंट प्लांट जैसी दोहरे उपयोग (डुअल-यूज) वाली सुविधाएं भी दिखाई देती हैं.

भारत सरकार ने हालिया चीनी घुसपैठ के दावों को खारिज किया है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भारतीय सेना का कहना है कि इस क्षेत्र में सीमा का औपचारिक निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए दोनों देशों की छअउ को लेकर अलग-अलग धारणा है. रिजिजू के मुताबिक, ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की गश्त कभी-कभी एक-दूसरे के दावे वाले क्षेत्रों तक पहुंच जाती है, जिसे 'ट्रांसग्रेशन' कहा जाता है, न कि घुसपैठ.

विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा पर चीन का तेजी से बढ़ता बुनियादी ढांचा भारत के लिए रणनीतिक चुनौती है. इसी के जवाब में भारत भी अरुणाचल प्रदेश में सड़क, सुरंग और अन्य सीमा अवसंरचना परियोजनाओं गणित चल रहा होगा. वो मौके की को तेजी से आगे बढ़ा रहा है.

क्या कहता है PIB Fact Check?

कई बार सही खबर को भी अलग कॉन्टेक्स्ट में पेश कर दिया जाता है और फर्जी धारणाएं बना ली जाती है. अगर आपके सामने भी ऐसा कोई संदिग्ध वीडियो, फोटो या दावा आता है, तो उसे बिना जांचे-परखे आगे साझा करने से बचें. पहले उसके स्रोत की पुष्टि करें और देखें कि क्या किसी आधिकारिक एजेंसी ने उस पर जानकारी जारी की है. गलत जानकारी को आगे बढ़ाना अनजाने में अफवाहों को बढ़ावा दे सकता है.

हारे हुए आसिम मुनीर को कहां से मिल रहा भारत को धमकाने का कॉन्फिडेंस? यूक्रेन का वो कांड तो नहीं जिम्मेदार

(जीएनएस)।

भारत की सीमाओं पर 'ऑपरेशन सिंदूर' और अपने करीब 600 ड्रोन्स के सुपरफ्लॉप होने के बाद बौखलाए पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अब सिंधु जल समझौते को रद्द करने की धमकियां दे रहे हैं और जंग की बातें कर रहे हैं. लेकिन इस पूरी नाकामी के बाद मुनीर की सेना को अचानक यह नया कॉन्फिडेंस आखिर मिल कहां से रहा है? सोशल मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच उड़ती खबरों की मानें तो भारत से करारी शिकस्त झेलने के बाद अब पाकिस्तान ने रूस के साथ भीषण जंग में तपे यूक्रेन का हाथ थाम लिया है, जहां यूक्रेन की सेना पाकिस्तानी मिलिट्री को आधुनिक ड्रोन ऑपरेशन्स की सीक्रेट ट्रेनिंग दे रही है.

पाकिस्तान के ह्यफेल्ड मार्शलह्ण आसिम मुनीर सिंधु नदी समझौता रद्द होने से बौराए हुए हैं. वो जंग के मूड में नजर आ रहे हैं और ह्यहर तरीका इस्तेमालह्ण करने की धमकी दे रह हैं. मजेदार बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब मुनीर को इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? कहीं इसके पीछे यूक्रेन का वो कांड तो नहीं है, जिसे भारत ने कुछ महीनों पहले नाकाम कर दिया था. भारत की सीमा पर अपने करीब 600 ड्रोन गंवाने के बाद अब रिपोर्ट्स हैं कि यूक्रेन, पाकिस्तानी मिलिट्री को ट्रेन कर रहा है. अब सवाल ये है कि यूक्रेन आखिर मुनीर सेना को आखिर ऐसा क्या सिखा रहा?

पिछले साल पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ अब तक की सबसे

बड़ी और आधुनिक साजिश रचने की कोशिश की थी. पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं के भीतर महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने के लिए एक साथ करीब 600 ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था लेकिन पाकिस्तानी सेना का ये पूरा ड्रोन ऑपरेशन एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ.

पाकिस्तानी सेना के ज्यादातर ड्रोन या तो भारतीय सेना ने सीमा पर ही मार गिराए या फिर वे तकनीकी कमियों की वजह से खुद ही क्रैश हो गए. हालांकि, कुछ ड्रोन्स का मलबा रिहायशी इलाकों में गिरने से आम नागरिकों को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान के इस ह्यमेगा ड्रोन प्लानह्ण को पूरी तरह मटियामेट कर दिया. इस करारी हार ने पाकिस्तानी सेना को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी मौजूदा तकनीक भारत के सामने बेहद कमजोर है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली हार और बार-बार फेल हुई भारत के खिलाफ साजिशों के बाद कमजोरी को छिपाने और आधुनिक ड्रोन वॉरफेयर सीखने के लिए पाकिस्तान ने अपने पुराने सहयोगी देश यूक्रेन का रुख किया. यूक्रेन पिछले कई सालों से रूस के खिलाफ एक बेहद भीषण और हाई-टेक युद्ध लड़ रहा है, जिसमें ड्रोन तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है.

यूक्रेन, पाकिस्तान को क्या सिखा रहा?

लगातार चल रही इस जंग ने यूक्रेन को ड्रोन ऑपरेशन्स, कामिकेज ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दुनिया का सबसे अनुभवी और ह्यबैटल-हार्डन्डह्ण देश बना दिया है. अब यूक्रेन अपने इसी युद्ध के कड़वे अनुभव और महारत को एक ह्यकमर्शियल एसेटह्ण यानी पैसे कमाने के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. पाकिस्तान इस ड्रोन ट्रेनिंग एक संजीवनी बूटी मान रहा है, जिससे वो भारत के हाथों मिली शिकस्त का बदला लेने का सपना देख रहा है और यही वजह है कि जनरल मुनीर का कॉन्फिडेंस अचानक सातवें आसमान पर नजर आ रहा है.

यूक्रेन ने पहले भी दिया है क्ल्र्ल्रि को धोखा

इतिहास देखें तो सोवियत संघ से अलग होने के बाद स्वतंत्र देश बने यूक्रेन ने कई मौकों पर संयुक्त राष्ट्र (वठ) में भारत के खिलाफ रुख अपनाया था. चाहे भारत का परमाणु परीक्षण हो या फिर कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग, यूक्रेन के पुराने फैसले भारत के पक्ष में नहीं थे.

हालांकि, बाद के सालों में यूक्रेन की आधिकारिक नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला. यूक्रेन ने हमेशा ये माना है कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच का एक द्विपक्षीय मामला है, जिसे दोनों देशों को 1972 के शिमला समझौते के तहत आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए. यूक्रेन का यह रुख भारत की उस नीति के बिल्कुल अनुकूल है, जिसके तहत नई दिल्ली किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता या कश्मीर मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण का कड़ा विरोध करती है

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की हुई शादी, दूल्हे राजा रोहन ठक्कर के साथ वेडिंग फोटो

(जीएनएस)।

बॉलीवुड के फेमस कपूर परिवार में एक बार फिर शहनाइयों की गूंज सुनाई दी है। फिल्ममेकर बोनी कपूर की बेटी और एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी कर ली है। दोनों की शादी की पहली झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। दूल्हा-दुल्हन के रूप में अंशुला और रोहन की जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया है।

शादी की तस्वीरों में दिखी खास केमिस्ट्री

सामने आई तस्वीरों और वीडियोज में अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। शादी के हर पल में दोनों के चेहरे पर नई जिंदगी की शुरूआत की चमक साफ दिखाई दे रही है। फेरे लेते वक्त भी अंशुला कपूर की मुस्कान कैमरे में कैद हुई थी, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में दोनों की बॉन्डिंग और खुशी साफ झलक रही है। फैंस भी इस जोड़ी को

'मेड फॉर इच अदर' बता रहे हैं और उन्हें नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं।

दुल्हन के लुक में छा गई अंशुला कपूर

अपने खास दिन के लिए अंशुला कपूर ने पारंपरिक अंदाज को चुना था। उन्होंने खूबसूरत और भारी कढ़ाई वाला लहंगा पहना था, जिसने उनके ब्राइडल लुक को बेहद आकर्षक बना दिया था। मांग टीका, स्टेटमेंट नेकलेस और लाल दुपट्टे के साथ उन्होंने अपने लुक को पूरा किया था। वहीं दूल्हे राजा रोहन ठक्कर भी किसी से कम नहीं लगे। उन्होंने हरे रंग की शेरवानी पहनकर शाही अंदाज में एंट्री की थी। दोनों की जोड़ी ने शादी समारोह की रौनक और बढ़ा दी थी।

अनिल कपूर समेत परिवार के कई सदस्य बने गवाह

-शादी समारोह में कपूर परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त मौजूद रहे। वायरल वीडियोज में एक्टर अनिल कपूर भी मेहमानों के साथ बातचीत करते नजर आए। सफेद शेरवानी में उनका अंदाज हमेशा की तरह आकर्षक दिखा।

-परिवार के बीच आयोजित इस समारोह में खुशियों का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि इस शादी को बेहद निजी रखा गया था लेकिन इसकी झलकियां सोशल मीडिया पर आते ही चर्चा का विषय बन गईं।

कपूर परिवार की खास कहानी

-जानकारी के अनुसार अंशुला कपूर फिल्म मेकर बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना शौरी कपूर की बेटी हैं। अर्जुन कपूर उनके बड़े भाई हैं। मोना शौरी के निधन के बाद परिवार ने कई उतार-चढ़ाव देखे। बाद में बोनी कपूर ने एक्ट्रेस श्रीदेवी से शादी कर ली थी, जिनसे उनकी दो बेटियां, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं।

-समय के साथ परिवार के रिश्तों में भी गहराई आई। श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर का रिश्ता जाह्नवी और खुशी के साथ और मजबूत होता गया। आज चारों भाई-बहनों के बीच खास बॉन्डिंग देखने को मिलती है।

मेहंदी और चूड़ा सेरेमनी बनी चर्चा का केंद्र

शादी से पहले अंशुला कपूर की मेहंदी और चूड़ा सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियोज भी खूब वायरल हुए थे। बताया जा रहा है कि जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर ने मिलकर अंशुला के लिए एक खास सरप्राइज प्लान किया था, जिसने इस समारोह को और भी यादगार बना दिया था। मेहंदी समारोह में अंशुला नीले रंग की खूबसूरत ड्रेस में नजर आई थीं जबकि चूड़ा सेरेमनी के दौरान उन्होंने हरे रंग का पारंपरिक परिधान चुना था। दोनों ही लुक्स को फैंस ने काफी पसंद किया है।

स्टार्स से सजा शादी का जश्न

-अंशुला और रोहन की प्री-वेडिंग रस्मों में बॉलीवुड के कई जाने-माने चेहरे भी शामिल हुए थे। करिश्मा कपूर, नीतू कपूर और वरुण धवन समेत कई सितारे इस खास मौके का हिस्सा बने थे। परिवार और दोस्तों की मौजूदगी ने इस शादी को और भी यादगार बना दिया है।

-अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी कपूर परिवार के लिए एक बेहद खास और भावुक पल रही। शादी की खूबसूरत तस्वीरों और वीडियोज ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। फैंस इस नई जोड़ी को ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की कामना कर रहे हैं।

सीएम योगी के आदेश पर ड्राइविंग लाइसेंस कर्मियों की शिकायत की जांच शुरू, परिवहन आयुक्त ने बनाई दो सदस्यीय समिति

(जीएनएस)।

लखनऊः परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य कर रही निजी कंपनियों से कथित तौर पर नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच गई. पिछले चार माह से विभागीय अधिकारियों और मंत्रियों के स्तर पर न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित कर्मचारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में अपनी व्यथा सुनाई थी. इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिकायत पर परिवहन विभाग को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने, पीड़ित को न्याय दिलाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर तीन दिन के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग हरकत में आ गया है. परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति गठित कर दी है. समिति में अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) मयंक ज्योति और एआरटीओ (प्रशासन) बाराबंकी अमिताभ राय को शामिल किया गया है. दोनों अधिकारियों को मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. समिति अपनी जांच रिपोर्ट बुधवार को परिवहन आयुक्त को सौंप सकती है. इस

प्रकरण को लेकर परिवहन मुख्यालय के अधिकारियों से बात की गई तो एक सीनियर अधिकारी ने नाम डिस्क्लोज न करने की शर्त पर बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फिलहाल नीरज यादव की शिकायत की जांच के निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसलिए विभाग का पूरा फोकस शिकायत की जांच पूरी कर निर्धारित समय में रिपोर्ट भेजने पर है.

अन्य पीड़ित कर्मचारियों की शिकायतों पर भी निर्देश प्राप्त होते हैं तो उन मामलों की भी नियमानुसार जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पीड़ित कर्मचारियों का आरोप है कि ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य कर रही निजी कंपनियों ने बिना ठोस कारण कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया. उनका कहना है कि पिछले चार माह से वे परिवहन विभाग के अधिकारियों, संबंधित मंत्रियों और अन्य स्तरों पर न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब पूरे मामले की जांच शुरू होने से कर्मचारियों में निष्पक्ष कार्रवाई और न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. बता दें कि शिकायतकर्ता नीरज यादव के साथ अखिलेश कुमार, अनुज कुमार , मुनेश, धर्मवीर सहित अन्य पीड़ित कर्मचारियों ने भी मुख्यमंत्री से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने और दोषी कंपनियों व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई थी. फिलहाल अब जांच शुरू हो गई है. कर्मचारियों को न्याय मिलने को उम्मीद है और कंपनियों को अपने ऊपर कारवाई होने का डर.

उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन का कहना है कि मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है बारीकी से टीम जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इसके बाद आगे कोई कदम उठाया जाएगा.

यूपी में शिक्षकों की बड़ी मुराद होने जा रही पूरी, चुनाव से पहले सीएम योगी ने चला बड़ा दांव

उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को वाराणसी से 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' की शुरूआत करेंगे. इस योजना के लागू होने के बाद शिक्षकों और उनके परिवारों को इलाज के लिए अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा.

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और उनके आश्रितों के लिए बड़ी राहत की खबर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को सुबह 10 बजे वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे. इस योजना के शुरू होते ही सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने लगेगी.

इस योजना का सबसे बड़ा

फायदा यह होगा कि इलाज के समय शिक्षकों और उनके परिवारों को अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. तय अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे आर्थिक बोझ काफी कम होगा. लंबे समय से शिक्षक इस तरह की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की मांग कर रहे थे.

इसके साथ ही प्रदेश के करीब 1.10 करोड़ परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये भी भेजे जाएंगे. यह राशि यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, बैग, स्वेटर और अन्य जरूरी शैक्षणिक सामग्री के लिए दी जाएगी. इसके अलावा करीब 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के साथ सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य लाभ भी दिए जाएंगे, जिससे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी.

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को दोपहर 2 बजे चित्रकूट और मानिकपुर में 951 करोड़ रुपये की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे. इन परियोजनाओं के जरिए सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी ने सुलतानपुर को दी 819 करोड़ की सौगात, विकास कार्यों से बदलेगी जिले की तस्वीर

(जीएनएस)।

सुलतानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्कस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने के पहले बटन दबाकर सुलतानपुर व इसौली विधानसभाओं में 81,900.37 रुपये की लागत से 65 परियोजनाओं का लोकार्पण व 34 कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी व मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से जिला प्रगति पर आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने सुलतानपुर विधानसभा में 43466.78 लाख रुपये की लागत से 32 तथा इसौली में 12234.80 लाख रुपये की 33 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा सुलतानपुर में 25321.53 लाख रुपये की लागत से 29 तथा 877.26 लाख से पांच परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या-प्रयागराज, वाराणसी-लखनऊ तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस की एक तिहाई

लंबाई जिले से गुजरने के कारण दूरियां सिमट गई हैं। परिणाम यह कि अयोध्या स्थित अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक पहुंचने में सिर्फ 45 मिनट का समय लग रहा है।

मंडलीय समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग की ओर से विधायकों द्वारा प्रस्तावित जिले में विकास कार्यों से संबंधित 16 अरब की विकास योजनाएं मुख्यमंत्री को सौंपी गई। जनसभा में संबोधन में प्रस्ताव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने इसे जल्द स्वीकृति का भरोसा दिलाया।

योजना के अनुसार सुलतानपुर, सदर, कादीपुर, लम्भुआ, इसौली व जगदीशपुर आंशिक में सड़क, सेतु व हेलीपैड संबंधी 904 कार्य संबंधित विधायकों द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। इन पर 16 अरब 66 करोड़ 45 लाख 15 हजार रुपये खर्च होंगे।

इन प्रस्तावों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए 509 सड़कों का नव निर्माण शामिल है। इन पर 57,769.39 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा ब्लाक व तहसील मुख्यालयों व धर्मार्थ सड़कों के नव निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल हैं।

18.800 किमी लंबे 18 मार्गों का चौड़ीकरण तथा 16 सड़कों पर सड़क सुरक्षा कार्य भी कराए जाने हैं। छोटे व मध्यम 48 सेतु पर कार्य समेत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 12 हेलीपैड भी बनाए जाने हैं। 287 क्षतिग्रस्त सड़कों का पैच मरम्मत भी कार्ययोजना में शामिल किया गया है।

एम्बुलेंस योजना में घोटाले का किया खुलासा, तो पत्रकार के घर इनकम टैक्स की रेड, बीजेपी सांसद पर आरोप

(जीएनएस)।

झारखंड के देवघर में एक पत्रकार के घर इनकम टैक्स (IT) की छापेमारी ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मामला उस समय और गरमा गया जब पत्रकार चमन कुमार ने दावा किया कि उन्होंने गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की चर्चित 'नमो एम्बुलेंस' योजना में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर खबरें प्रकाशित की थीं।

पत्रकार का आरोप है कि उन्हीं खबरों की वजह से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। हालांकि, आयकर विभाग ने अभी तक इस कार्रवाई को पत्रकार की रिपोर्टिंग से जोड़ने की पुष्टि नहीं की है।

पत्रकार चमन कुमार का कहना है कि उन्होंने 'नमो एम्बुलेंस' योजना में कथित वित्तीय गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार से जुड़ी कई खबरें प्रकाशित की थीं। उनके मुताबिक, इन खबरों के बाद लगातार उन पर दबाव बनाया गया। अब उनके घर हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई को भी वह उसी कड़ी का हिस्सा बता रहे हैं। उनका आरोप है कि सत्ता से जुड़े लोगों के खिलाफ खबर लिखने की कीमत उन्हें और

उनके परिवार को चुकानी पड़ रही है।

पत्रकार चमन कुमार ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनके घर पर हुई आईटी रेड का मकसद टैक्स जांच नहीं, बल्कि उन्हें डराना और चुप कराना है। उनका दावा है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल आलोचनात्मक पत्रकारिता को दबाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। आयकर विभाग ने भी अभी तक यह नहीं कहा है कि कार्रवाई का संबंध किसी खबर या पत्रकारिता से है।

निशिकांत दुबे की ओर से क्या कहा गया?

इस पूरे विवाद पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से फिलहाल कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले भी वह अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं। दूसरी ओर, उनके समर्थकों का कहना है कि जांच एजेंसियां अपने तय नियमों के तहत काम करती हैं और किसी कार्रवाई को सीधे सांसद से जोड़ना उचित नहीं होगा। मामले पर सभी पक्षों की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

निशिकांत दुबे के खिलाफ सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

आईटी रेड की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि सत्ता के खिलाफ खबर लिखने वाले पत्रकारों को डराने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने पत्रकार चमन कुमार के समर्थन में पोस्ट करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। हालांकि, दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि यदि आयकर विभाग के पास कार्रवाई के पर्याप्त आधार हैं तो जांच को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर बहस लगातार तेज होती जा रही है।

'मोदी सरकार ने ई-20 पेट्रोल पर ऑटो कंपनियों से बुलवाया झूठ', केजरीवाल का बड़ा हमला

(जीएनएस)।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों पर ई-20 पेट्रोल थोपने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रही मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑटो कंपनियों मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प ने झूठ बुलवाया कि ई-10 वाहन में ई-20 के इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं होगा।

जबकि टोयोटा, मारुति सहित अन्य कंपनी ने ओनर मैनुअल में माना है कि 10 फीसदी से ज्यादा एथेनॉल इस्तेमाल नहीं करना है, फिर भी दिक्कत आए तो इसे भी नहीं करना है। उन्होंने कहा कि मैं सभी ऑटो कंपनियों को चिट्ठी लिखूंगा और लिखित में मांगूंगा कि ई-20 से गाड़ी की माइलेज गिरने या पार्ट्स खराब होने की भरपाई करने का आश्वासन दें।

अगले हफ्ते मैं पीएम को भी चिट्ठी लिखूंगा और पूछूंगा कि अगर किसी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो उसका हजार्ना सरकार देगी या कंपनी? मंगलवार को "आप" मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश पर जबरदस्ती ई-20 पेट्रोल थोप रही है। लोगों का जबरदस्त विरोध है, लेकिन इस विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी हुई है।

केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रहीः केजरीवाल

उस जिद्द का कारण क्या है, यह तो नहीं पता, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। रोज झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, कभी एक मंत्री झूठ बोल रहा है, तो कभी दूसरा मंत्री। झूठ के पुलिंदे दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लोगों को मनाने और यह समझाने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि वे ई-20 इस्तेमाल कर लें।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने छह ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बुलाया और कहा कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताएं कि ई-20 ठीक है। ये छह कंपनियां मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर कंपनी हैं। इन सभी से कहा गया कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जनता को बताएं कि ई20 सही पेट्रोल है। अगर किसी का व्हीकल ई-10 है, तब भी ई-20 चलेगा। उनका व्हीकल ई-20 नहीं है, तब भी चलेगा। उनका व्हीकल अगर ई-0 या ई-5 पर चलने वाला है, तब भी ई-20 पेट्रोल चलेगा।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इन छह में से तीन कंपनियों ने सरकार को यह कहते हुए मना कर दिया कि वे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकतीं। लेकिन मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प ने प्रेस कांफ्रेंस में जनता से झूठ बोला। इन तीनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर किसी का व्हीकल ई-0, ई-5 या ई-10 है और अगर वे उसमें ई-20 पेट्रोल डाल दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 5-7 फीसदी माइलेज गिरेगी, लेकिन फ्यूल टैंक, फ्यूल सिस्टम और इंजन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इन तीनों कंपनियों ने जनता से झूठ बोला। जब लोग गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी के साथ एक ओनर मैनुअल मिलता है। उसमें सारी शर्तें होती हैं। वह एक तरह से उपभोक्ता और ऑटो कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है।

अरविंद केजरीवाल ने ई-20 वाहन के बारे में बताते हुए कहा कि 2023 से पहले जितने व्हीकल बने हैं, जो एथेनॉल के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध पेट्रोल के लिए बने थे, उनमें अगर 10 फीसद एथेनॉल इस्तेमाल भी कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं होती। उन्हें ई-10 कंप्लायंट बोलते हैं। 2023 से पहले बने हुए व्हीकल, जिनमें या तो शून्य एथेनॉल या 10 फीसदी तक एथेनॉल इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे ई-10 बोलते हैं। 2023 के बाद से भारत में सारे व्हीकल ई-20 बनने लग गए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ये कंपनियां कहती हैं कि ई-20 इस्तेमाल कर लें, ई-10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कंपनियों ने झूठ बोला। मैं इन तीनों से कहना चाहता हूं कि अपने ग्राहकों को धोखा मत दो। अपने ग्राहकों से झूठ मत बोलो। सरकारें आती-जाती रहती हैं। वैसे भी यह सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ग्राहक ही राजा होता है। अगर लोगों ने उनका माल खरीदना बंद कर दिया, तो उसके बाद वे कहां जाएंगे?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुधवार को मैं झूठ बोलने वाली इन तीनों कंपनियों को चिट्ठी लिखूंगा और उनसे कहूंगा कि उनका ओनर मैनुअल तो यह कहता है और वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहते हैं। वे लिखित में दे दें कि अगर किसी गाड़ी की माइलेज 10 फीसदी से ज्यादा कम हो जाती है, तो क्या वे उस व्यक्ति को माइलेज के लिए मुआवजा देंगे? अगर ई-20 इस्तेमाल करने से गाड़ी खराब हो जाती है या टूट-फूट होती है, तो क्या वे उस गाड़ी के पुर्जे को बदलने का मुआवजा देंगे? वे एक बार हां कह दें, पूरे देश में उनके प्लांट के सामने गाड़ियों की लाइन लग जाएगी।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं दूसरी कंपनियों को भी चिट्ठी लिखूंगा, जिन्होंने सरकार के कहने के बावजूद झूठ नहीं बोला। उनसे बस यह पूछूंगा कि एक बार स्पष्ट कर दें कि क्या वे भी मानते हैं कि ई10 में ई20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता? बुधवार को मैं सभी कंपनियों को एक चिट्ठी लिखूंगा और अगले हफ्ते प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा कि उनके इस गलत कदम का नुकसान जनता क्यों भुगते? वे यह बता दें कि अगर लोगों की गाड़ी का माइलेज कम होता है, तो हजार्ना उनकी सरकार देगी या कंपनी देगी? अगर लोगों की गाड़ी का इंजन या फ्यूल सिस्टम खराब होता है, तो हजार्ना तो देना ही पड़ेगा। जनता हजार्ना क्यों भुगते? हजार्ना मोदी जी की सरकार देगी या कंपनी देगी?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने एक और झूठ चला रखा है कि भारत कोई पहला देश थोड़ी है जो एथेनॉल इस्तेमाल कर रहा है और भी बहुत से देश हैं जो एथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां तो लोग शोर नहीं कर रहे। यह आधा सच है। बाकी देशों में जो एथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है, वह ई10 से कम हो रहा है। नॉर्मल गाड़ियां भी ई10 तक तो इस्तेमाल कर लेती हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पातीं। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और थाईलैंड में अभी तक ई10 से कम इस्तेमाल होता है।

अरविंद केजरीवाल ने आगे बताया कि जापान में ई3 इस्तेमाल होता है और वहां ई10 का टारगेट 2030 रखा गया है। उन्होंने 7-8 साल का फेज आउट पीरियड दिया है। ई3 से ई10 तक जाने के लिए जापान ने 7 साल रखे हैं। ई20 का टारगेट जापान ने 2040 रखा है। आज से 16 साल बाद ई20 में जाने के लिए जापान 16 साल का समय लेगा। थाईलैंड ने 2008 में ट्रायल और पायलट बेसिस पर कुछ पेट्रोल पंपों पर ई20 ट्राई किया था। आज 2026 हो गया है, 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां दोनों विकल्प मौजूद हैं।

भारत ने दबाई नस तो तिलमिलाया पाकिस्तान, हमला करने की देने लगा धमकी, क्या है वजह?

(जीएनएस)।

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते (क्लल४िर हंशी१ ळ१्रीं३८) को लेकर तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने साल 1960 के इस ऐतिहासिक समझौते सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान में इस फैसले को लेकर टेंशन बनी हुई है। पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी केवल पानी का एक जरिया नहीं बल्कि उसकी खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में भारत के रुख ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों की चिंता बढ़ा दी है।

सिंधु के पानी पर आगबबूला हुआ पाक

इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अध्यक्षता में सैन्य कमान की बैठक हुई। बैठक के बाद पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि देश के जल अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की नीति के मुताबिक हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। सेना का कहना है कि वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

दरअसल, यह बयान पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (ठरउ) की उस नीति के अनुरूप है, जिसमें भारत की ओर से पानी रोकने की किसी भी कोशिश को 'युद्ध की कार्रवाई' (अ३ ड्ड हं१) माना गया है। इसी बैठक में सैन्य अधिकारियों ने अपनी तैयारियों का जायजा लिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की रणनीति पर भी चर्चा की।

बिलावल ने दी भारत को धमकी देने मे

पानी के मुद्दे पर पाकिस्तान के राजनीतिक नेताओं की ओर से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (ढढढ) के

अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि सिंधु जल समझौते को लेकर विवाद और बढ़ता है तो पाकिस्तान हर स्तर पर जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पानी को रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

उधर भारत ने अपना रुख दोहराते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से पैदा होने और चलाए जाने वाले आतंकवाद पर असरदार कार्रवाई नहीं करता, तब तक सिंधु जल समझौते की सामान्य व्यवस्था बहाल नहीं की जाएगी।

क्या है सिंधु जल समझौता?

साल 1960 में World Bank की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर साइन हुए थे। इस समझौते के तहत रावी, सतलुज और ब्यास जैसी पूर्वी नदियों का इस्तेमाल भारत करता है, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी पश्चिमी नदियों का अधिकांश जल पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। ऊपरी धारा वाला देश (वस्र्स्री१ फ्र्रं१ल्ल र३ं३ी) होने के कारण भारत मानसून के दौरान पाकिस्तान के साथ बाढ़ से जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा भी साझा करता था। लेकिन समझौते की सामान्य प्रक्रियाएं स्थगित होने के बाद भारत ने यह जानकारी साझा करना भी रोक दिया है।

भारत तेज कर रहा अपने हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट

सिंधु बेसिन में भारत अब अपनी कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। इनमें सावलकोट, रतले, बुर्सर, पकल दुल, क्वार, किरू और कीर्थाई जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भारत अपनी सीमा के भीतर जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और इस्तेमाल की क्षमता बढ़ा सकेगा। एक्सपर्ट्स की मानें तो इन परियोजनाओं से भारत को ऊर्जा उत्पादन और जल प्रबंधन दोनों क्षेत्रों में फायदा मिलेगा। वहीं पाकिस्तान की ओर से इस पर लगातार चिंता जताई जा रही है।

80-90% पाकिस्तान सिंधु पर निर्भर

पाकिस्तान की करीब 80 से 90 प्रतिशत कृषि सिंधु नदी पर निर्भर करती है। यही वजह है कि पानी से जुड़ा हर फैसला वहां की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान के पास पानी संग्रह करने की क्षमता सीमित है और वह लगभग एक महीने की जरूरत के बराबर ही पानी सुरक्षित रख सकता है। देश के दो बड़े जलाशय तरबेला और मंगला बांध भी कम जलस्तर की चुनौती का सामना कर रहे हैं।

भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है। उसने विभिन्न वैश्विक संस्थानों और कानूनी मंचों से भी संपर्क किया है। हालांकि भारत का कहना है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक सिंधु जल समझौते की सामान्य प्रक्रियाओं को बहाल करने का सवाल नहीं उठता।

बात होगी या होगा युद्ध?

सिंधु जल समझौता दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों में गिना जाता है। मौजूदा हालात में यह केवल जल प्रबंधन का विषय नहीं रह गया है, बल्कि कूटनीति, सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति से भी जुड़ चुका है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि दोनों देश इस विवाद को बातचीत के जरिए आगे बढ़ाते हैं या तनाव और बढ़ता है। फिलहाल भारत अपने घोषित रुख पर कायम है, जबकि पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा है।